

Fluctuation in prices of Essential Commodities

6903. Shri Madhu Limaye:
Shri S. M. Banerjee:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri George Fernandes:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether Government have made a comparative study of the fluctuations in prices of essential commodities, including food articles, in the Congress States and the non-Congress States;

(b) whether it is a fact that anti-hoarding measures taken by the Non-Congress Governments have proved effective in bringing down the prices;

(c) if so, whether Government propose to advise the Congress Government to adopt such anti-hoarding measures; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Anti-hoarding measures are taken by both the Congress and the non-Congress Governments, as and when necessary. Statewise price trends in recent months do not indicate more favourable trends in States with non-Congress Governments than in other States.

(d) Does not arise.

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी

6904. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० न० तिवारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार के सिन्धु जम्पारन में रक्सौल में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित केन्द्रीय बांध पड़ताल चौकी के विरुद्ध देशी विदेशी तस्करी बढ़ गई है कि वह

सामान की तस्करी में सक्रिय रूप से सहयोग दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) तथा (ख). भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल तथा अन्य पड़ताल चौकियों से होकर तीसरे देश के बने सामान के चोरी छिपे रूप में लाये ले जाने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारत तथा नेपाल के बीच हुई व्यापार और परिवहन संधि, 1960 में इन दोनों देशों में से किसी भी देश के माल के सीमा के आर-पार स्वतंत्र रूप से लाने ले जाने की व्यवस्था है और इसलिए कोई नियमित सीमा-शुल्क नाके बंदी नहीं की गई है। लेकिन इस सीमा पर 17 पड़ताल चौकियां हैं जो मुख्यतः भारत में बने ऐसे सामान की पहचान करने तथा उसे प्रमाणित करने के लिए स्थापित की गई हैं, जिस पर उत्पादन शुल्क की छूट नेपाल के महामहोमी सरकार को देय होती है अथवा ऐसे विदेशी माल की पहचान करने और उसे प्रमाणित करने के लिए हैं जो जो सीमा शुल्क बाण्ड के अन्तर्गत लाया ले जाया जाता है। ऐसा पता लगा है कि इन दिनों नेपाल दूसरे देशों से उपभोक्ता माल का आयात कर रहा है और उसमें से कुछ माल सीमा से होकर भारत में आ गया है। यद्यपि इस प्रकार माल चोरी छिपे लाने ले जाने को रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है तथापि नियमित सीमा-शुल्क नाकाबन्दी न होने से तथा सीमा पर कर्मचारियों की सीमित संख्या होने से चोरी छिपे रूप में यदाकदा माल लाने ले जाने को नहीं टाला जा सकता। जहाँ तक सरकार को विदित है यह काम केवल छोटे पैमाने पर ही हुआ है और अधिकतर उन लोगों द्वारा किया गया है जो सीमा के निकट रहते हैं। भारत-नेपाल सीमा पर रक्सौल तथा अन्य स्थानों